

द्वपिक्षीय नविश संधियाँ

प्रलिमिंस के लयि:

[द्वपिक्षीय नविश संधियाँ \(BITs\)](#), [केंद्रीय बजट 2024-25](#), [प्रत्यक्ष वदिशी नविश \(FDI\)](#) ।

मेन्स के लयि:

द्वपिक्षीय नविश संधियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था के लयि FDI का महत्त्व ।

[स्रोत:इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्योँ?

अंतरमि [केंद्रीय बजट 2024-25](#) प्रस्तुत करते हुए, भारतीय वतित मंत्री ने कहा कि भारत [प्रत्यक्ष वदिशी नविश \(Foreign direct investment- FDI\)](#) के प्रवाह को बढ़ावा देने के लयि अपने व्यापरकि भागीदारों के साथ [द्वपिक्षीय नविश संधियाँ \(Bilateral Investment Treaty- BITs\)](#) पर बातचीत करेगा ।

- वशिष रूप से वर्ष 2016 में [BIT मॉडल](#) को अपनाने के बाद से भारत की द्वपिक्षीय संधियाँ समाप्त हो गई हैं ।

द्वपिक्षीय नविश संधियाँ (BITs) क्या हैं?

- परचिय:**
 - BITs दो देशों के बीच एक-दूसरे के क्षेत्रों में वदिशी नजिी नविश को बढ़ावा देने एवं उसकी सुरक्षा करने के लयि पारस्परकि समझौते हैं ।
 - 90 के दशक के मध्य से भारत सरकार ने वदिशी नविशकों एवं नविशों को अनुकूल परस्थितियों के साथ संधि-आधारित सुरक्षा प्रदान करने के लयि BIT की शुरुआत की ।
- न्यूनतम गारंटी:**
 - BIT वदिशी नविश व्यवहार के संबंध में **दोनों देशों के बीच न्यूनतम गारंटी स्थापति** करते हैं, जैसे,
 - राष्ट्रीय व्यवहार** (वदिशी नविशकों के साथ घरेलू कंपनियों के समान व्यवहार करना)
 - नषिपक्ष एवं न्यायसंगत व्यवहार** (अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार)
 - जब्तती से सुरक्षा** (प्रत्येक देश की अपने क्षेत्र में वदिशी नविश प्राप्त करने की क्षमता को सीमति करना) ।
- BITs के अंतरगत मध्यस्थता:**
 - BITs सामान्य रूप से नविशकों एवं नविश करने वाले देश के बीच **वविादों को नपिटाने के लयि एक तंत्र** प्रदान करते हैं ।
 - ऐसे वविादों को नपिटाने के लयि सर्वाधिक चुना जाने वाला तरीका मध्यस्थता है, जहाँ पक्ष न्यायालय में जाने के स्थान पर अपने वविाद का नरिणय किसी तटस्थ व्यक्त (मध्यस्थ) द्वार कराये जाने पर सहमती व्यक्त करते हैं ।
- इतहास:**
 - भारत द्वारा **पहला BITs, वर्ष 1994 में UK के साथ हस्ताक्षरति** कयिा गया था ।
 - वर्ष 2010** में भारत के खिलाफ दायर **पहली नविशक संधि दावे के नपिटाने के साथ BITs संधिने ध्यान आकर्षति** कयिा ।
 - वर्ष 2011 में भारत को **ऑस्ट्रेलया-भारत BITs (व्हाइट इंडस्ट्रीज़ बनाम रपिब्लिक ऑफ इंडया)** से उत्पन्न वविाद में अपना पहला प्रतकिल भुगतान करना पड़ा, जहाँ भारत सरकार को इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 4.1 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दयिा गया था ।
 - वर्ष 2015 तक भारत को 17 ज्ञात BITs दावों का सामना करना पड़ा, जसिमें ब्रिटिश तेल और गैस कंपनी **केयर्न एनर्जी Pic** का दावा भी शामिल था, जसिके परिणामस्वरूप भारत सरकार को 1.2 बलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मलिा ।
 - सरकारी खजाने पर बढ़ रहे बोझ को देखते हुए, सरकार वर्ष 1993, **BIT मॉडल** पर फरि से वचिार करने के लयि वविश हुई । इसके

परिणामस्वरूप वर्ष 2016 मॉडल BIT को अपनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने संशोधित पाठ के आधार पर शर्तों पर पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ वर्ष 2015 तक नष्टिपादति 74 संधियों में से 68 को समाप्त कर दिया।

- वर्ष 2016, BIT मॉडल को अपनाने को वदिशी नविश को प्रोत्साहति करने के लिये एक सूक्ष्म तथा कैलबिरेटेड (अंशांकति) दृष्टिकोण के स्थान पर एक तत्काल संरक्षणवादी उपाय के रूप में देखा गया था।

वर्ष 2016 मॉडल BIT के साथ क्या चुनौतियाँ रही हैं?

- नविश की संरक्षित परभाषा:**
 - BIT मॉडल द्वारा BIT सुरक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करने के लिये आवश्यक नविश की परभाषा को सीमति कर दिया। BIT मॉडल इंगति करता है कि भारत नविश के लिये एक संकीर्ण 'उद्यम-आधारित' परभाषा को प्रस्तावति करता है, जिसके तहत संधि के तहत केवल प्रत्यक्ष नविश को संरक्षित किया जाता है।
 - इसमें एक नकारात्मक सूची भी शामिल है, जो नविश की परभाषा से पोर्टफोलियो नविश, ऋण-प्रतभूतियों में ब्याज, अमूर्त अधिकार इत्यादि को अलग करती है।
 - इस प्रकार नई परभाषा वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के आधुनिक युग में वदिशी नविश के बढ़ते दायरे को ध्यान में नहीं रखती है।
- घरेलू उपचार खण्ड की समाप्तति:**
 - BIT मॉडल में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने से पूर्व घरेलू उपचार की समाप्तति को अनविर्य करने वाला एक खंड शामिल है।
 - वर्ष 2016, BIT मॉडल में प्रावधान किया गया है कि एक नविशक को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेने से पूर्व स्थानीय व्यवहार का उपयोग करना होगा।
 - यह नश्चिति रूप से वदिशी नविशकों में वशिवास बढ़ाने के लिये बहुत कम है।
- FDI पर प्रभाव:**
 - अन्य देशों के साथ शर्तों पर पुनः बातचीत करने में आने वाली कठिनाइयों ने भी FDI को आकर्षित करने में चुनौतियों में योगदान दिया है।
 - अप्रैल-सितंबर 2023 में भारत में FDI इक्वटी प्रवाह 24% घटकर 20.48 बलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
 - कुल FDI- जिसमें इक्वटी प्रवाह, पुनर्नविश आय तथा अन्य पूंजी शामिल है, अप्रैल-जून 2022 में 38.94 बलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले समीक्षाधीन अवर्ध के दौरान 15.5% घटकर 32.9 बलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।
- मेज़बान राज्य को व्यापक वविकाधीन शक्तियाँ:**
 - संधि में नविश के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने वाला एक खंड शामिल था, जो दोनों पक्षों को ऐसे उपायों को लागू करने से रोकता है जो स्पष्ट रूप से अपमानजनक हैं या उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं।
 - हालाँकि, "उचित प्रक्रिया" के उल्लंघन के मूल्यांकन का पैमाना क्या है, यह परभाषित नहीं किया गया है।
 - इसके अतिरिक्त BIT मॉडल में कहा गया है कि यदि मेज़बान राज्य यह नरिणय लेता है कि BIT के तहत कथित उल्लंघन किसी भी समय कराधान का वषिय है, तो मेज़बान राज्य का नरिणय गैर-न्यायसंगत होगा और साथ ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा समीक्षा से छूट दी जाएगी।
 - मॉडल BIT मानता है कि एक वदिशी नविशक को घरेलू न्यायिक व्याख्याओं एवं तंत्रों पर पूर्ण वशिवास होगा।
 - यह संभावित रूप से मेज़बान राज्य को किसी भी वविाद को न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से एकतरफा बाहर करने का व्यापक अधिकार दे सकता है, केवल इस आधार पर कि प्रश्न में आचरण कराधान से संबंधित है।

आगे की राह

- वदिशी नविशकों और घरेलू अर्थव्यवस्था दोनों के हितों को संतुलित करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिये कि यत्नश्वकित सर्वात्तम प्रथाओं के साथ संरेखित हो, भारत अपनी BIT व्यवस्था पर फरि से वचिार कर सकता है। इसमें नष्टिपक्ष एवं न्यायसंगत व्यवहार, सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा एवं मज़बूत वविाद समाधान तंत्र के प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
- वविादों के समय पर नष्टिपक्ष के सुवधि के साथ नविशक राज्य वविादों में प्रभावी प्रतनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2021 में वदिशी मामलों पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सफिराशियों, जैसे मध्यस्थता पूर्व परामर्श एवं बातचीत को बढ़ावा देने के साथ लागू करना।
- भारत को नविशक राज्य वविादों को प्रभावी ढंग से संभालने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिये नविश मध्यस्थता के क्षेत्र में स्थानीय वशिषज्जता वकिसति करने में नविश करना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण पेशेवरों एवं कानूनी वशिषज्जों को शामिल किया जा सकता है, साथ ही नविश मध्यस्थता के लिये वशिष संस्थान भी बनाए जा सकते हैं।
- भारत को BIT के लिये एक प्रगतशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जो नयिमक संप्रभुता की अनविर्यता के साथ नविशक सुरक्षा की आवश्यकता को संतुलित करता है। इसमें नविशकों के अधिकारों के साथ-साथ सतत् वविकास, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों को भी शामिल किया जा सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: नमिनलखिति पर वचिार कीजिये: (2021)

- वदिशी मुद्रा परविरतनीय
- कुछ शर्तों के साथ वदिशी संस्थागत नविश
- वैश्वकित डिपोजिटरी रसीदें

4. अनवासी बाहरी जमा

उपर्युक्त में से कसिको प्रत्यक्ष वदिशी नविश में शामिल कया जा सकता है?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 4
- (d) केवल 1 और 4

उत्तर: (a)

भारत का अक्षय ऊर्जा वज़िन: IREDA

प्रलिमिस के लयि:

[पेरसि समझौता](#), भारत का अक्षय ऊर्जा वज़िन: IREDA, [वशिव बैंक \(WB\)](#), जलवायु परविरतन

मेन्स के लयि:

भारत का अक्षय ऊर्जा वज़िन: IREDA, वभिन्नि क्षेत्रों में वकिस के लयि सरकारी नीतयिँ और हस्तक्षेप एवं उनकी रूपरेखा तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

[स्रोत: पी.आई.बी](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में [भारतीय अक्षय ऊर्जा वकिस संस्था लिमिटेड \(IREDA\)](#) ने [वशिव बैंक \(WB\)](#) द्वारा आयोजति एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधति कया जसिमें भारत के अक्षय ऊर्जा परदृश्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चति करते हुए जलवायु परविरतन से निपटने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया ।

वेबिनार में IREDA के संबोधन से संबंधति प्रमुख बदि कया हैं?

- **जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति हेतु भारी नविश:**
 - वर्ष 2030 के लयि भारत के [राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान \(NDC\)](#) अथवा [पेरसि समझौते](#) के तहत इसकी जलवायु संबंधी प्रतजिज्ञाओं की पूर्ति के लयि 30 लाख करोड़ रुपए के नविश की आवश्यकता होगी ।
 - भारत के NDC लक्ष्यों के अनुसार भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने [सकल घरेलू उत्पाद \(GDP\)](#) की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने और वर्ष 2030 तक [गैर-जीवाश्म ईधन-आधारति ऊर्जा स्रोतों से वदियुत उत्पादन की लगभग 50% संचयी स्थापति क्षमता](#) हासलि करने के लयि प्रतबिद्ध है ।
 - **सौर ऊर्जा**, इलेक्ट्रोलाइज़र, पवन और बैटरी स्पेस, पावर ट्रांसमशिन, [ग्रीन हाइड्रोजन](#), हाइड्रो पावर तथा अपशषिट-से-ऊर्जा क्षेत्रों में वनिर्माण एवं क्षमता वसितार के लयि नविश की आवश्यकता है ।
- **रूफ टॉप सोलर क्षेत्र का उन्नयन:**
 - IREDA ने वेबिनार में रूफ टॉप सोलर योजना ["PM सूर्य घर मुफ्त बजिली योजना"](#) के महत्त्व पर प्रकाश डाला ।
 - उक्त दूरदर्शी परयोजना में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का नविश कया गया है । जसिका लक्ष्य प्रत्येक माह 300 यूनिट तक मुफ्त बजिली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से लैस करना है ।
 - यह योजना लोगों को न केवल पर्याप्त लाभ प्रदान करती है अपत्ति अक्षय ऊर्जा के बारे में उनकी जागरूकता भी बढ़ाती है जो [वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन](#) और वर्ष 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनरिभर बनने के भारत के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य में योगदान देती है ।
- **ऊर्जा मांग में वृद्धि:**
 - IREDA के अनुसार देश के लयि [सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं के कारण](#) भारत की ऊर्जा मांग में महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी तथा अधिकतम ऊर्जा मांग की पूर्ति [अक्षय/नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से की जाएगी](#) ।
 - ऊर्जा मांग के लगभग 90% की पूर्ति नवीकरणीय स्रोतों से की जाएगी ।
 - नवीकरणीय ऊर्जा के लयि पर्याप्त ऊर्जा भंडारण का पर्यास जारी है कत्ति इसकी प्राप्ति तक थर्मल ऊर्जा का भी वकिस कया

IREDA क्या है?

- भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (IREDA) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार का एक [मनी रतन प्रतिष्ठान](#) है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1987 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये एक विशेष [गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान](#) के रूप में की गई थी।
- IREDA नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो वित्तीय संस्थानों/बैंकों को इस क्षेत्र में ऋण प्रदान करने का विश्वास दिलाता है।

अक्षय ऊर्जा से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

- [नवीकरणीय खरीद दायित्व \(Renewable Purchase Obligations- RPO\)](#)
- [PM-कृषुम योजना](#)
- [सौर PV निर्माण के लिये PLI योजना](#)
- [नवीकरणीय ऊर्जा के लिये स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक FDI की अनुमति](#)
- [अटल ज्योती योजना](#)
- [अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन](#)
- [वन सन, वन वरलड, वन ग्रडि \(OSOWOG\)](#)
- [राष्ट्रीय सौर मशिन](#)
- [सूर्यमत्त कौशल विकास कार्यक्रम](#)
- [प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना](#)
- RE परसिंपत्तियों के लिये 'मसूट रन' स्थिति:
 - 'मसूट रन' स्थितिका आशय संबंधित वदियुत संयंत्र को सभी परस्थितियों में ग्रडि को वदियुत की आपूर्तिकराने से है।

और पढ़ें...[IEA की इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट](#), [इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030: IEA](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिये गए कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. भारत प्रकाश- वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सलिकॉन वेफर्स का दुनयिा में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
2. सौर ऊर्जा शुल्क का नरिधारण भारतीय सौर ऊर्जा नगिम के द्वारा कयिा जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- सलिकॉन वेफर्स अर्द्धचालक के पतले सलाइस होते हैं, जैसे- क्रसिटीय सलिकॉन (c-Si), एकीकृत/इंटीग्रेटेड सर्कटि का नरिमाण और प्रकाश- वोल्टीय सेल के नरिमाण के लिये उपयोग कयिा जाता है। चीन अब तक सलिकॉन का दुनयिा का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील का स्थान है। भारत सलिकॉन एवं सलिकॉन वेफर्स के शीर्ष पाँच उत्पादकों में शामिल नहीं है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- सौर ऊर्जा शुल्क का नरिधारण केंद्रीय वदियुत नयिमक आयोग द्वारा कयिा जाता है, न कि भारतीय सौर ऊर्जा नगिम द्वारा। अतः कथन 2 सही नहीं है।

अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में 'नेट मीटरिंग' (Net metering) नमिनलखिति में से कसिको प्रोत्साहति करने के संदर्भ में देखा जाता है। (2016)

- (a) परिवारों/उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग
- (b) घरों की रसोईघरों में पाइप प्राकृतिक गैस का उपयोग
- (c) मोटरगाड़ियों में CNG कटि लगवाना
- (d) शहरी घरों में पानी के मीटर लगवाना

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न. भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएँ हैं, हालाँकि इसके विकास में कषेत्रीय भन्नताएँ हैं। वसितुत वर्णन कीजिये। (2020)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/19-02-2024/print>

